P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* (Supplementary Issue) July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

श्रीमती इन्दिरा गाँधी का कृषि उत्पादन क्षेत्र में आर्थिक दर्शन

अशोक कुमार
असिसटेंट प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
चरखारी, महोबा, उ0प्र0

सारांश

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश अंग्रेजों के अधीन होने के कारण विकास नहीं कर सका। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में पं0 जवाहर लाल नेहरु एवं लाल बहादुर शास्त्री के काल में कुछ विकास हुआ परन्तु वर्ष 1962 के चीन आक्रमण 1965 के भारत – पाक युध्द एवं 1965–1966 में देश व्यापी सूखा पड़ने से देश की अर्थ व्यवस्था चौपट हो गई वर्ष 1964 में नेहरु जी एवं जनवरी 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु हो चुकी थी ऐसी विषम परिस्थितियों में वर्ष 1966 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने प्रधानमंत्री के रुप मे देश की बागडोर संभाल ली उन्होंने देश में खाद्यान्न समस्या के समाधान एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि में नवीन तकनीकों– उन्नत किस्म के बीज, देशी खाद के साथ रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाईयाँ आदि के उपयोगों पर बल दिया। जिससे कृषि में आशातीत वृध्दि हुई जिसे हरित क्रान्ति का नाम दिया गया। तत्पश्चात आगामी योजनाओं में भी कृषि विकास पर ध्यान देने के कारण देश आयात से निर्यात की दश में पहुँच गया।

मुख्य शब्द : खाद्यान्न समस्या, कृषि, पंचवर्षीय योजनाएं।

प्रस्तावना

भारत में वर्ष 1947 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य था। ब्रिटिश शासक भारतीयों तथा भारत की सम्पत्ति का उपयोग स्वदेश ब्रिटेन के विकास हेतु करते थे। यह योजना भारतीय देशभक्तों जैसे––राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, सरदार बल्लभ भाई पटेल भगत सिंह चन्द्रशेखर आजाद दादा भाई नौरोजी नेताजी सुभाश चन्द्र बोस गोविन्द रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मी बाई, पं0 जवाहर लाल नेहरु आदि को रास नहीं आई। सभी ने मिलकर देश को विभिन्न आन्दोलनों जैसे – अंग्रेजो भारत छोड़ो करो या मरो, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, खिलाफत आन्दोलन आदि एवं ब्रिटिष लोगों द्वारा दी गई विभिन्न क्रूरतम यातनायें सहन करते हुए एवं कुर्बानियों के माध्यम से एवं सत्य अहिंसा के बल पर भी देश को 15 अगस्त 1947 को अंग्रजों के चंगुल से पूर्णतया मुक्त घोषित कर दिया तत्पष्चात देश की शासन सत्ता भी वर्ष 1947 में पं0 जवाहर लाल नेहरु ने संभाली। वर्ष 1947 को डा0 राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता एवं महान कानून विद् एवं विद्वान डा0 भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में गठित संविधान सभा द्वारा देश में संविधान का निर्माण किया गया जिसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। भारतीय संविधान के नियमानुसार प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरु के नेतृत्व में देश की परिस्थितिनुसार वर्ष 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1966 तक पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृशि, द्वितीय में औद्योगिक विकास, तृतीय में औद्योगिक उत्पादों के निर्यात पर बल देना था परन्तु वर्ष 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण, 1965 में भारत पाक युद्ध,वर्ष 1965 – 1966 में देश भर में भयंकर सूखा, वर्ष 1964 में नेहरु जी की मृत्यु आदि के कारण देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। सत्ता पलटने के कारण लाल बहादुर षास्त्री ने भी प्रधान मंत्री के रुप में देश का विकास किया। जनवरी 1966 में उनका भी आकस्मिक निधन हो गया। वर्ष 1966 में ही लोकतांत्रिक विधि से देश की शासन सत्ता प्रधानमंत्री के रुप में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के हाथों में उपलब्ध हो गई। उन्होंने विरासत में नवीन तकनीकी रुप में प्राप्त विषम परिस्थति में योजनाबद्ध विधि से कृषि विकास हेतु उन्नत किस्म के बीज देशी खाद एवं रासायनिक उर्वरक ,पोटाष, कीटनाषक, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक कृषि यन्त्र उपकरण के रुप में हल बैल के स्थान पर ट्रैक्टर, थ्रेसर, हारवेस्टर, डीजल पम्प सैट, भूमि सुधार ऋण सुविधा हेतु बैंकों का राश्ट्रीय करण, राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति आदि उपायों को अपनाया गया जिसके परिणाम स्वरुप कृषि उत्पादन में प्रचुर वृद्धि हुई जिसे

हरित क्रान्ति का नाम दिया गया जिसका उपयोग देश में खाद्यान्न आपूर्ति में किया गया। अतिरिक्त उत्पाद को निर्यात करने हेतू विचार किया जाने लगा। जिसका श्रेय श्रीमती इन्दिरा गाँधी को ही जाता है।

अध्ययन का उददेश्य

आजादी के बाद देश में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के शासन काल में नवीन तकनीकी का प्रयोग कर कृषि उत्पादन में प्रचुर वृद्धि हुई जिसकी देश विदेशों में सराहना हुई। जिसे हरित क्रान्ति का नाम दिया गया। खाद्यान समस्या समाधान के साथ निर्यात करने की परिस्थति उत्पन्न हुई। इसलिए मैंने भी कृषि उत्पादन दर्शन पर शोध करने का निष्चय कर लिया।

शोध पद्धति

इसमें उपर्युक्त के अतिरिक्त कृषि के कार्य वर्ष 1966 से योजनावार छठवीं पचवर्षीय योजना में श्रीमती गाँधी के काल में कृषि उत्पादन में उपलब्धि को उनके द्वारा समय–समय पर दिये गये वक्तव्यों एवं निश्कर्श के रुप में शोध किया गया है।

कृषि

कृषि से अभिप्राय कृशकों के यहाँ उपलब्ध विभिन्न उत्पादन साधनों के पारस्परिक एंव मानवगतसम्बन्धों को नियमित करने की विधियों पर विचार करने एंव उसे कार्यरुप में क्रियान्वित करने से है जिसके द्वारा उत्पादन से उपभोक्ताओं की खाद्यान्न सन्तुश्टि एवं कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति की जा सके।

यदि किसी देश की अधिकांष जनसंख्या कृषि एंव सम्बद्ध क्रियाओं जैसे ... पषुपालन, बागवानी ए मत्स्यपालन ए मुर्गी पालन आदि मे संलग्न हों राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र के उत्पादन से प्राप्त होता हो तथा विदेशी व्यापार की संरचना में कृषि उत्पादकों का विषिश्ट महत्व हो तब ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि ये देश साधनों व तकनीकी ज्ञान के अभाव में औद्योगिक विकास द्वारा विकसित अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः यह सोचकर कि यदि कृषि कार्य में लगातार लगे रहेंगे तो कभी न कभी औद्योगिक विकास के लिए साधनों व तकनीकी जानकारी की उपलब्धि स्वतः ही हो जायेगी इसी लक्ष्य की प्राप्ति की आषा से लोग कृषि व सम्बन्धित कार्यों में जुटे रहते हैं। अस्तु ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को विकासषील अर्थव्यवस्था के रुप में माना जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था मानी जाती है। उपर्युक्त विशेषता उस देश की अर्थव्यवस्था में विद्यमान है। जहाँ की लगभग 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं सम्बद्ध कार्यों में संलग्न रहती है। कृषि से ही सभी मनुश्यों को भोजन, पषुओं को चारा तथा देश की जनसंख्या के विशाल भाग को रोजगार उपलब्ध होता है। इसका मुख्य कारण कृषि व्यवसायों का समुचित रुप से विकसित न होना है। क्योंकि आजादी से पूर्व शताब्दियों से भारत विदेशियों के शासन से ग्रसित रहा है। जिनका उददेश्य भारत की भूमि में उत्पादित उपज को स्वदेशी उद्योगों को सुदृढ़ करने के लिए कच्चे माल के रूप में कम कीमतों पर बेचना स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को भारतियों को श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद देश की सत्ता की बागडोर श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों में आ गई। उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तथा खाद्य समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी। वर्ष 1962 के चीन आक्रमण, 1965 में भारत व पकिस्तान युद्ध से क्षतिग्रस्त आर्थिक स्थिति के कारण देश में कृषि में सिचांई व अन्य साधनों का अभाव हो गया था। 1965–66 में ही देशव्यापी सूखा पड़ने के कारण कृशि उत्पादन में भारी गिरावट होने से गम्भीर खाद्य संकट था। कृषि क्षेत्र की यह असन्तोशजनक स्थिति अन्य क्षेत्रों के विकास में भी बाधक सिद्ध हुई। भुगतान सन्तुलन में घाटा बहुत अधिक हो गया। जून1966 में विष्व बैंक व अमेरिका के दबाब में आकर भारत को रूपये का अवमूल्यन करना पड़ा। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में गम्भीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी लेकिन इन समस्याओं की संकटपूर्ण स्थिति में साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा था कि– We have innumerable problems requiring urgentAction. The rains have failed causing drought in many parts of the country. So to today weAre facing with food shortAges not in one state but in many parts of the country.AsA result inAgricultural, which is still precariously dependent on weatherAnd rain fall has suffered A sharp decline. Let us not be dismayed or discourage by these unforeseen difficulties. Let us we have to face them boldly.

अतः खाद्य समस्या को प्राथमिकता देकर षीघ्रातिषीघ्र समाधान हेतु भारत में षान्ति के लिए खाद्य धारा पी.एल. 480 के अन्तर्गत अमेरिका से भारत में खाद्यानों का आयात किया गया। अतः इस स्थिति का श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक चुनौती के रूप में सामना किया। एक तरफ उन्होंने खाद्यानों का आयात किया तथा दूसरी तरफ कृषि के विकास के लिए पहले से षुरु किये गये विभिन्न कार्यक्रमों जैसे–गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1961, उच्च उत्पादक बीज कार्यक्रम 1963 ,सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम 1964 को व्यापक स्तर पर अपनाने पर बल दिया तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 1963 एवं भारतीय खाद्य निगम व कृषि मूल्य आयोग 1965 को अपने कार्य में तेजी लाने की अनुमति भी दी तथा कृषकों को अधिक से अधिक कृषि सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने के लिए कृशक प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम 1966 षुरु कराया।

कृषि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्रीमती गांधी के नेतृत्व में सरकार ने देश में आर्थिक विकास के लिए पुनः कृषि एवं सिंचाई विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष 1966 से 1969 तक तीन वार्षिक योजनाओं के अनुसार कार्य किया। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के बारे में श्रीमती गांधी ने कहा था कि ''देश का सम्पूर्ण विकास औद्योगिक विकास सहित कृषि में उत्पादित उपज पर निर्भर है।'' जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है कि :

Priority is given to naturally because the whole development including industrial development dependent on what happens in the Agriculture Sphere.

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* (Supplementary Issue) July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

इसके अतिरिक्त कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का दूसरा कारण बताया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य कार्यक्रमों के क्षेत्र में वृद्धि और सिंचाई के विस्तार से वर्ष भर में लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे फलतः इसका लाभ ग्रामीणों को मिलेगा व बेरोजगारी की समस्या हल हो सकेगी। जैसा की श्रीमती गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि – Rural employement is helped byAgricultural programmesAndAsAgriculture production goes up there will be more opportunity for employement in ruralAreas. Thus extension of irrigation and increase in theArea under multiple croppingAnd other measures of this kind can provide more remunerative employment round the year in the rural Areas.

इसलिए श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार ने वर्ष 1965 व 1966 में अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों जिसमें गेहूँ, चावल,ज्वार,बाजरा,मक्का का सिंचाई साधनों के विस्तार व रासायनिक देशी उर्वरकों व कीटनाषकों, कृषि यन्त्रों, उपकरणों आदि के प्रयोग करने से सूखा के संकट को सहन करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान दिया फिर वर्ष 1967 में देश व्यापी सूखा पडी फिर भी कृषि उत्पादन की सफलता से प्रभावित होकर 1966–1969 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र पर किये गये कुल व्यय रु 6757 करोड़ रुपये में से 1624 करोड़ रुपये व्यय किये गये। कृषि उपज की प्रगति निम्न प्रकार रही थी। वर्ष 1966 से 1969 तक की एक वार्षिक योजनान्तर्गत कृषि प्रगति। वर्ष 1965–66 से 1968–69 तक (वार्षिक कृषि प्रगति)

फसलें	उत्पादन लक्ष्य 1965–66	वास्तविक उत्पादन 1965–66	वास्तविक उत्पादन 1968–69
खाद्यान (लाख टन में)	100.0	72.0	94.0
तिलहन (लाख टन में)	9.8	6.4	6.8
गन्ना (लाख टन में)	10.0	12.7	12.8
कपास (लाख गाठें)	7.0	4.6	5.1
जूट (लाख गाठें)	6.2	4.5	6.3

तालिका से स्पष्ट है कि तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष 1965–66 में विभिन्न कृषि उपजों सहित खाद्यानों का उत्पादन नींचा रहा फिर वर्ष 1967–68 में मौसम की अनुकूलता एवं सिंचाई साधनों की व्यवस्था, उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक एवं देशी उर्वरकों के प्रयोग पर क्षमता अनुसार व्यय करने से वर्ष 1968–69 में कृषि में प्रगति देखने को मिली।

इस अवधि में सरकार ने क्षमतानुसार 56 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की तथा 40 लाख हैक्टेयर भूमि पर संरक्षण कार्य हुआ। 92 लाख हैक्टेयर भूमि पर अच्छे बीजों की सहायता से फसलें तैयार की गयी।1.8 लाख नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाष आदि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया उक्त सभी के परिणाम स्वरुप वर्ष 1968–69 में खाद्यानों (लाख टन में), गन्ना (लाख टन में) कपास व जूट (लाख गाठें) का वास्तविक उत्पादन क्रमषः 94.8 , 6.8 , 12.8 , 5.1 ,6.3 रहा। जो वर्ष 1965–1966 के वास्तविक उत्पादन से उधिक था जिसे सरकार ने कृषि सम्बन्धी नवीन नीति या हरित क्रान्ति की संज्ञा दी। क्योंकि सरकार का विचार था कि उसने खाद्य समस्या का स्थायी हल खोज लिया उसने यह घोशणा की कि नवीन कृषि नीति से देश में हरित क्रान्ति आई है लेकिन श्रीमती इन्दिरा गाँधी को यह बात पसंद नही आई क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि सूखा वाले क्षेत्रों में सिंचाई,उर्वरक व खादें एवं बौनी किस्म के उन्नत बीजों, कीटनाषक दवाइयों, कृषि यन्त्रों, उपकरणों के प्रयोग को बढावा देने के लिए हुई है। वास्तविक सिंचाई का विस्तार होता जा रहा है, सूखा वाले क्षेत्रों मे सघन कृषि के लिए नये कार्यक्रम लागू किये हैं जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा साथ ही हम वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर ध्यान दे रहे है जैसा कि इनके वक्तव्य से स्पष्ट है –

I do not like very much the word “green revolution” but it is true that we have made very great progress inAgriculture and we have irrigated land that is now over 35 millionAcres. But with all this the revolution as you call it, is limited toAbove one fifth of the irrigated land. Of course the irrigation progamme is goingAhead quite fast And now we have initiated new programme for intensive Acriculture in the dry Areas providing them special varieties of seeds And fertilizers And these programmeAre labour intensive so that they will have in providing employment Also weAreAlso paying specialAttention to commercial crops but As you know industrial Advance is necessary for better Agriculture.

इस प्रकार तीन वार्षिक (1966 से 1969) योजनाओं में देश में कृषि उपज में हुई आशातीत वृद्धि से प्रभावित होकर अधिकाधिक उत्पादन करने पर बल दिया। परिणामतः चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969से1974) में देश के आर्थिक विकास पर किये गये सकल व्यय रु0 15779 करोड में से 2320 करोड़ रुपये 14.7 प्रतिशत कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र पर व्यय किया गया तथा कृषि क्षेत्र में 5 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया लेकिन 1960–1961 की कीमतों पर औसत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित लक्ष्य से कम अर्थात 3.3 प्रतिशत वार्षिक रही। वर्ष 1969–70 व 1970–71 उत्पादन की दृश्टि से सन्तोश जनक रहे किन्तु 1971–72 में मामूली गिरावट आई। 1972–73 में बहुत कमी हो गई। वर्ष 1973–74 में कुछ सुधार हुआ। कृषि उत्पादन सम्बन्धी सूचकांक के अनुसार वर्ष 1973–74 के लिए कृषि उत्पादन के लक्ष्य एवं वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार रहे।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* (Supplementary Issue) July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

मदें / इकाई	उत्पादन लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
खाद्यान (लाख टन)	1290	1407
कपास (लाख टन)	80	63
जूट (लाख गांठें)	74	62
तिलहन (लाख टन)	105	89
गन्ना (लाख टन)	150	144

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना–1969–74

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि चतुर्थ योजना में खाद्यान को छोड़कर षेश सभी के उत्पादन लक्ष्य से नींचे रहे थे। इस प्रकार कृषि की स्थिति प्रतिकूल होने पर हरित क्रान्ति का प्रभाव भी धीरे–धीरे समाप्त होता गया।

पांचवी योजना 1974–79 में कुल व्यय 39303 करोड़ रुपये में से कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र पर 463 करोड़ रुपये व्यय किये गये जिसमें कृषि उत्पादन में आत्म निर्भरता को प्राथमिकता दी गई। फलतः पांचवी योजना में वर्ष 1974–79 में कृषि उत्पादन 15.3 प्रतिशत बढ़ा वर्ष 1976–77 में 6.7 प्रतिशत की कमी रही। वर्ष 1977–78 में कृषि उत्पादन फिर बढ़ा पांचवी योजना में कृषि उत्पादन की स्थिति निम्न प्रकार रही –

पांचवीं पंचवर्षीय योजना(1974–79)तक

कम सं0 / मदें	**इकाई**	**1974–75**	**1975–76**	**1976–77**	**1977–78**
खाद्यान	**लाख टन**	998	1213	1112	1264
कपास	**लाख गांठें**	72	60	58	72
जूट / मेस्ता	**लाख गांठें**	58	59	71	72

पांचवी योजना 31 मार्च 1979 को समाप्त होनी थी लेकिन वर्ष 1977–78 में देश की शासन सत्ता की बागडोर जनता सरकार के हाथों में आने के कारण पाँचवी योजना एक वर्ष पूर्व अर्थात 31 मार्च 1978 को ही समाप्त कर दी गयी। तथा सरकार ने 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 तक के लिए छठी योजना निर्धारित कर दी लेकिन 1980 में कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने पर जनता सरकार की छठी योजना समाप्त करके नई छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 निर्धारित कर दी छठी योजना के प्रलेख में यह उल्लेख किया गया कि छठी योजना की विकास एवं विधि में कृषि तथा उद्योग दोनों की अधःसंरचना को अनिवार्यतः एक साथ मजबूत किया जायेगा ताकि विनियोग, रोजगार एवं उत्पादन में त्वरित वृद्धि के लिए परिस्थितियां कायम की जा सकें।

छठवी पंचवर्षीय योजना में 97500 करोड़ रुपये के सार्वजनिक व्यय में से 12539 करोड़ रुपये अर्थात 12.3 प्रतिशत कृषि एवं सम्बन्धित कार्यों पर व्यय किया गया। कृषि उत्पादन की वृद्धि दर निर्धारित लक्ष्य के बराबर रही तथा 1979–80 में देश की राष्ट्रीय आय में कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र का हिस्सा 40.6 प्रतिशत था परन्तु चावल, गेहूँ, दालें एवं अन्य अनाजों के मध्य असन्तुलन बना रहा क्योंकि सिंचित क्षेत्र केवल 31 प्रतिशत था तथा 26.3 कि0 ग्रा0 प्रति हैक्टेयर रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया था।

छठी योजना के दौरान ही खाद्यानों में अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों के अधीन क्षेत्रफल वर्ष 1979–80 में 352 लाख हैक्टेयर था जो वर्ष 1984–85 में बढ़कर 560 लाख हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि का श्रेय श्री मती इन्दिरा गाँधी सरकार को ही है।

निष्कर्ष

देश में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अपेक्षा वर्ष 1966 के बाद श्रीमती इन्दिरा गाँधी के शासन काल में कृषि क्षेत्र में परम्परागत के स्थान पर नवीन आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि को बढावा मिला जिससे न केवल खाद्यान समस्या हल हुई वरन् निर्यात वृध्दि को प्रोत्साहन मिला जिसकी भारत सहित विष्वभर में सराहना की गई जो कि सभी के लिए अनुसरण हेतु प्रेरणा का स्रोत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *The years of challenge (selected speechers of Indira Gandhi)- Jan. 1966 toAug. 1969.page no.5, Publication Division Ministry of InformationAnd Broadcasting,Govt. of India New Delhi.*
2. *The years of challenge (Selected speeches of Indira Gandhi)- Jan. 1966 toAug. 1969.page no.4,Publication Division Ministry of InformationAnd Broadcasting,Govt. of India New Delhi.*
3. *The years of challenge (Selected speeches of Indira Gandhi)- Jan. 1966 toAug. 1969. Page no.122-123 Publication Division Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India New Delhi.*
4. *चतुर्थ पंचवर्षीय योजना।*
5. *इकोनोमिक सर्वे 1980–81 पेज न0 79.*
6. *छठी योजना प्रलेख से।*
7. *इकोनोमिक सर्वे 1980–81 पेज न0 66.*
8. *द इकोनोमिक टाइम्स जुलाई 25 1981.*
9. *V. M. Dandekar, submission to the forces of the market, in L.M. Singhri (Ed.) Devaluation of the Rupee its ImplicationsAnd consequences (N.M.) page 94.*